किसकी अनुमति से लगे ये होर्डिंग, एमसीएफ को मालूम नहीं

मजदूर मोर्चा ब्यूरो

फरीदाबादः हरियाणा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओमप्रकाश धनखड़ अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार पिछले हफ्ते फरीदाबाद में आए। उनकी आवभगत में जिला भाजपा अध्यक्ष गोपाल शर्मा आसमान से तारे तो तोड़कर नहीं ला सके लेकिन अपने प्रदेश अध्यक्ष को खुश करने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन इस मौके पर लगाए गए होर्डिंग्स से जिला भाजपा विवादों में आ गई है।

जिला भाजपा की ओर से धनखड़ के स्वागत में शहर में जगह-जगह तमाम सरकारी बोर्ड और साइनेज को ढांकते हुए होर्डिंग लगा दिए गए। इस खबर के जो फोटो दिया जा रहा है, वह मथुरा रोड पर बडखल पुल के ऊपर बने साइनेज को ढांकते हुए लगाया गया है। अगर कोई फरीदाबाद पहली बार आ रहा है और वो इस साइनेज के सहारे आगे बढ़ने की कोशिश करेगा तो धोखा खा जाएगा। बडखल पुल से केन्द्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर का सेक्टर 28 स्थित आवास बहुत नजदीक है। इसलिए इस पुल पर अक्सर किसी न किसी भाजपाई नेता का होर्डिंग लगा रहता है। इस संबंध में जब नगर निगम फरीदाबाद (एमसीएफ) में पूछताछ की गई तो उन्होंने इससे अनभिज्ञता जताई। उनका कहना था कि हमने होर्डिंग लगाने का ठेका कुछ विज्ञापन कंपनियों को दे रखा है, उन्हें पता होगा कि ये होर्डिंग किसकी अनुमति से लगाए गए हैं। लेकिन एमसीएफ अफसरों के पास इस सवाल का जवाब नहीं है कि शहर में बने साइनेज को ढांककर ऐसे होर्डिंग लगाने की अनुमति

तो कमिश्नर भी नहीं दे सकते। यह अपराध की श्रेणी में आता है। एमसीएफ चाहे तो इसकी एफआईआर करा सकता है।

एक तरफ तो सरकारी नियमों की धज्जियां उड़ाकर शहर में लगे साइनेज पर भाजपा के होर्डिंग, बैनर, पोस्टर लगाए जा रहे हैं, दूसरी तरफ भाजपा के नेता, मंत्री और पदाधिकारी एमसीएफ में फैले भ्रष्टाचार को लेकर बहुत चिंतित हैं। इन नेताओं ने भाजपा की विचारधारा को प्रचारित-प्रसारित करने वाले अखबार में खबर छपवाई है कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओमप्रकाश धनखड़, मंत्री मूलचंद शर्मा और केन्द्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने एमसीएफ में फैले भ्रष्टाचार पर बहुत चिन्ता जताई है। जल्द ही ये लोग एमसीएफ को ठीक करने के लिए कुछ करेंगे। उस खबर में ये भी कहा गया कि अभी तक एमसीएफ के बॉयलाज न बनने से ये सारे भाजपाई नेता हैरान हैं।

अब ये नेता एमसीएफ के बॉयलाज बनवाएंगे। लेकिन मजदूर मोर्चा को हैरानी इस बात पर है कि छह साल से एमसीएफ में भाजपा का कब्जा है। केन्द्रीय मंत्री गुर्जर का बेटा देवेन्द्र चौधरी वास्तविक मेयर है और भाजपा नेता कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए एमसीएफ के बायलाज बनवाएंगे। तो बड़ा सवाल यही है कि अभी तक बायलाज बनाने से क्या मजदूर मोर्चा या विपक्षी दलों ने रोका हुआ था?

बंगाल में अचानक उभरी आईएसएफ और फुरफुरा शरीफ का रिश्ता क्या है

कृष्णन अय्यर

बंगाल चुनाव में इंडियन सेकुलर फ्रंट (आईएसएफ) न रातोंरात पैदा हुआ और न कांग्रेस ने इसे बिना सोचे समझे लेफ्ट के साथ अपने गठबंधन में शामिल किया है। लेकिन जब कांग्रेस के अंदर से ही आईएसएफ को लेकर सवाल होने लगे तो इसकी तरफ नजर जाना ही है। मुसलमानों के स्वयंभू मसीहा असदद्दीन ओवैसी और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने भी आईएसएफ से गठबंधन की कोशिश की थी लेकिन कामयाबी नहीं मिली। आईएसएफ के बहाने भाजपा को बहुत सारे मौके मिल गए हैं। हर चुनाव में वह कांग्रेस को घेरने के लिए ध्रुवीकरण को यानी हिन्दू मुसलमान को लाती है और मैदान मार ले जाती है। अभी चुनाव की ठीक से शुरुआत भी नहीं हो पाई है कि भाजपा ने बंगाल में कांग्रेस, लेफ्ट और आईएसएफ गठबंधन में आईएसएफ को पाकिस्तानी, आतंकी, हिन्दू विरोधी और न जाने क्या क्या बोला जा रहा है...पूराना फॉर्मूला है : आतंकी बोलो, चुनाव जीतो। आईएसएफ से दरअसल लाभ किसको होगा, यह तस्वीर भी जल्द ही सामने आ जाएगी। टीएमसी को मुस्लिम मतदाताओं का समर्थन आईएसएफ से कितना प्रभावित होगा, ये देखना होगा।

बहरहाल, आइए जानते हैं कि दरअसल आईएसएफ है क्या...

आईएसएफ के प्रधान अब्बास सिद्दीकी बंगाल की एक दरगाह से जूड़े हुए है जिसका नाम है फुरफुरा शरीफ। सन् 1375 में यह स्थापित हुई थी यानी 600 साल से ज्यादा पुरानी दरगाह है..अजमेर शरीफ के बाद भारत की सबसे महत्वपूर्ण दरगाह का दर्जा माना जाता है।

इनके पुरखे अशरफी मुसलमान थे जो बंगाल में आए और यहां की मिट्टी में घुलमिल गए। आजादी की लड़ाई में भी इस दरगाह की बड़ी हिस्सेदारी रही। इनका काम है शिक्षा, हॉस्पिटल/अनाथ आश्रम चलाना और सामाजिक काम। 98 प्रतिशत हिन्दू इलाकों के बीच बसी ये दरगाह भारत की धरोहर है। बहुत बड़ी इज्जत है और धर्म के नाम पर कोई विभेद नही किया जाता। इनके 600 सालों के इतिहास मे इन पर कभी भी साम्प्रदायिक होने का आरोप नही लगा।

फुरफुरा शरीफ मुसलमानो में कोएजुकेशन को बढ़ावा देती है। इनके सारे स्कूल,कॉलेज कोएजुकेशन ही है। विज्ञान और आधुनिक शिक्षा का सिलेबस है। मदरसे भी है पर उनमें भी आधुनिक शिक्षा ही है।

बांग्ला/हिंदी/इंग्लिश शिक्षा का माध्यम है। दूसरी भाषाएं बहुत कम है। हिन्दू छात्र/छात्राओं की संख्या भी भरपूर है।

फुरफुरा शरीफ को तो आरएसएस की भी हिम्मत नही है कम्युनल बोलने की। मुझे बताया गया कि आरएसएस वाले इस दरगाह के धार्मिक प्रधान से मिलते रहते है।

600 साल में पहली बार इस दरगाह का कोई वंशज राजनीति में आया है, तो हलचल होना तय है। क्योंकि ये लोग प्रचार से दूर रहते है। अब राजनीति में हैं तो प्रचार भी होगा।

दलालों के माध्यम से बिजली विभाग में मची है लूट

ग्रीन फील्ड में बिजली निगम के दलाल से संपर्क करो, नहीं तो बिल से उड़ जाएगी नींद

मजदूर मोर्चा ब्यूरो

फरीदाबादः दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (डीएचबीवीएन) के अधिकारी-कर्मचारी मिलकर अनाप-शनाप बिजली का बिल भेज रहे हैं और जब मामला उठता है तो वे सारी जिम्मेदारी उस आउटसोर्सिंग कंपनी पर डाल देते हैं जो बिजली का बिल भेजती है। ग्रीन फील्ड कॉलोनी में आजकल यही हो रहा है। तमाम घरों में गलत बिजली बिल भेजे जा रहे हैं और यहां के लोग बिजली बोर्ड के एक्सईएन, एसडीओ के चक्कर लगाकर थक गए हैं लेकिन जनता को इधर से उधर घुमाने के अलावा और कुछ नहीं किया जाता है।

ग्रीन फील्ड कॉलोनी के ए ब्लॉक में तीन बीएचके फ्लैट में रहने वाली बिमला आहूजा को पहले पौने दो लाख का बिजली का बिल भेजा गया। जब उनके बेटे ने भागदौड़ शुरू की तो डीएचबीवीएन के अफसरों ने कहा कि ये बिल हिसार मुख्यालय से ठीक होकर आएगा। फिर एसडीओ मेहरा ने घर में लगे मीटर की जांच के लिए भेजा गया। वहां से रिपोर्ट आई की मीटर सही है। बिमला आहूजा के बेटे ने सेक्टर 15 में एक्सईएन के पास जाकर अपनी परेशानी बताई। वहां से एक्सईएन ने एसडीओ मेहरा से कहा कि आप कुछ पेमेंट जमा कराकर मामले का निपटारा करो। एसडीओ मेहरा ने कहा कि 1 लाख 45 हजार रुपये की पार्ट पेमेंट जमा करा दो। यह पैसा जमा करा दिया गया।

इसी दौरान बिजली विभाग के अफसरों ने बिमला आहूजा को सूचना दी कि डीएचबीवीएन ने 66 हजार 993 रुपये ज्यादा वसूले हैं लेकिन इस पैसे को आगामी बिलों में एडजस्ट किया जाएगा। बिमला आहूजा के बेटे ने बताया कि हम लोग यह समाहित कर दिया जाएगा लेकिन बिजली निगम ने 13 फरवरी 2021 में बिमला आहूजा को जो बिल भेजा वह करीब 54,000 रुपये का है। उसी समय से आहूजा परिवार के होश फाख्ता हैं कि पहले वाले

66 हजार एडजस्ट नहीं हुए और अब दोबारा से 54000 रुपये का बिल भेज दिया गया। अब ये लोग एसडीओ मेहरा के पास चक्कर लगा रहे हैं लेकिन उनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है।

ग्रीन फील्ड कॉलोनी में या तो नौकरीपेशा या फिर बिजनेस करने वाले लोग रहते हैं। ज्यादातर के काम दिल्ली में हैं। जिनके पास फरीदाबाद के सरकारी दफ्तर में चक्कर काटने का समय नहीं है। इसलिए ग्रीन फील्ड में स्थित तमाम सरकारी दफ्तरों में दलाल सिस्टम खड़ा हो गया है। बिजली विभाग इससे अछूता नहीं है। बिजली निगम में सक्रिय दलालों के जरिए काम कराने पर सारी समस्याएं हल हो जाती हैं लेकिन जो लोग शिकायत लेकर एक्सईएन तक चले जाते हैं, उनको परेशान किया जाना तय है।

हालांकि सेक्टर 15 और शहर के अन्य क्षेत्रों में बैठे एक्सईएन भी इसी दलाल सिस्टम से जुड़े हुए हैं लेकिन पद की वजह से उन्हें सुनवाई करनी ही पड़ती है। लेकिन वहां मामला सुलझाने की बजाय और उलझा दिया जाता है। बिजली मीटर अब बाहर खंभों पर टंगे हुए हैं। आउटसोर्सिंग कंपनी का कर्मचारी कब मीटर रीडिंग के लिए आता है, कोई नहीं जानता। सारे मीटर रीडरों के पास कैमरे हैं, उनमें वो किस तरह रीडिंग लेते हैं, जिनका बिल पौने दो लाख का आ जाता है, समझ से बाहर हैं। यहां रह रहे दो बीएचके फ्लैटों में दस-दस हजार रुपये के बिल आ रहे हैं। दलाल के जरिए संपर्क न करने पर उनके बिल सही नहीं किए जाते और उन पर बिल भरने का दबाव बनाया जाता है।

ये हाल सिर्फ ग्रीन फील्ड कॉलोनी का ही नहीं है। फरीदाबाद में बिजली विभाग के सारे दफ्तर दलालों के जरिए चलाए जा रहे हैं। इन दफ्तरों में न अफसर काम करके राजी हैं और न ही कर्मचारी। गलती से अगर कोई अधिकारी किसी कर्मचारी पर कार्रवाई करता है तो कर्मचारी यूनियन फौरन बचाव में आ जाती है।